भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.02.2026 के
तारांकित प्रश्न सं. 80 का उत्तर

देश में रेल डिब्बा विनिर्माण इकाइयां

***80. श्रीमती मंजू शर्मा:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में कितनी रेल डिब्बा विनिर्माण इकाइयां चल रही हैं;
(ख) देश भर में रेल डिब्बा विनिर्माण सुविधाओं के विकास पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में टियर-2 और टियर-3 शहरों में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(घ) सरकार द्वारा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में उच्च-गति के अनुकूल रेल पटरियों के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा पारंपरिक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) के डिब्बों के स्थान पर लिंके हॉफमैन बुश (एलएचबी) डिब्बों का इस्तेमाल किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 04.02.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 80 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): वर्तमान में, रेल मंत्रालय के अधीन देशभर में तीन सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयाँ संचालित की जा रही हैं।

सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयों के विकास की लागत विभिन्न कारकों जैसे अवस्थिति, विनिर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित सवारी डिब्बों का प्रकार, नियोजित उत्पादन क्षमता और संस्थापित की जाने वाली मशीनरी और संयंत्र पर निर्भर करती है। सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयों के विकास पर लंबी अवधि में और कई चरणों में व्यय उपगत किया जाता है, जिसमें इकाइयों की प्रारंभिक स्थापना के साथ-साथ समय-समय पर सुविधाओं के उन्नयन और संवर्धन भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए, नवीनतम चालू सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाई - आधुनिक सवारी डिब्बा कारखाना, रायबरेली की स्थापना पर 3,042.83 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

इसके अलावा, तीन चालू सवारी डिब्बा विनिर्माण इकाइयों अर्थात एकीकृत सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई, रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, और आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के उन्नयन/संवर्धन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2443 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

स्टेशन पुनर्विकास :

रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन करना शामिल है। मास्टर प्लान संरचित करने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन तक पहुँच और परिचलन क्षेत्रों में सुधार
- शहर के दोनों ओर स्टेशन का एकीकरण

- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और पेयजल-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स का प्रावधान
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैंप का प्रावधान
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/प्रावधान और प्लेटफ़ॉर्म को ऊपर से कवर करना
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान
- पार्किंग क्षेत्र, मल्टीमोडल एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक इस योजना के तहत विकास हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से गुजरात के 87 स्टेशनों और मध्य प्रदेश के 80 स्टेशन और राजस्थान के 85 स्टेशनों की पहचान की गई है।

अभी तक 172 स्टेशनों का कार्य पूरा किया जा चुका है, इनमें से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के जिन स्टेशनों पर कार्य पूरे कर लिए गए हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
गुजरात	21	डाकोर, देरोल, गोधरा जंक्शन, हापा, जाम जोधपुर, जाम वंथाली, कनालुस जंक्शन, करमसद, खंभालिया, कोसम्बा जंक्शन, लिम्बडी, महुवा, मीठापुर, मोरबी, ओखा, पालिताना, पोरबंदर, राजुला जंक्शन, समखियाली, सिहोर जंक्शन, उत्राण
मध्य प्रदेश	14	ब्यौहारी, भिंड, हरपालपुर, जुनौर देव, कटनी साउथ, एमसीएस छतरपुर, नैनपुर जंक्शन, नर्मदापुरम, ओरछा, सांची, सिवनी, शाजापुर, श्रीधाम, विदिशा
राजस्थान	12	बाड़मेर, बूंदी, देशनोक, फतेहपुर शेखवटी, गंगापुर सिटी, गोगामेरी, गोविंदगढ़, जैसलमेर, खैरथल, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, राजगढ़

अन्य स्टेशनों पर भी निर्माण कार्यों को तेज गति से शुरू किया गया है और इन राज्यों के कुछ स्टेशनों पर कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

- रीवा स्टेशन पर: स्टेशन भवन, प्रवेश और निकास द्वार बरामदे, जल निकासी में सुधार, नए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण और प्रतीक्षालय में सुधार के लिए कार्य पूरे किए जा चुके हैं। पार्किंग स्थल के प्रावधान के साथ परिचलन क्षेत्र में सुधार, 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल का प्रावधान और प्लेटफॉर्म संख्या 1 की सतह की ऊंचाई बढ़ाने और सतह को समतल करने के कार्य शुरू किए गए हैं।

- रुथियाई स्टेशन पर: स्टेशन भवन का सुधार कार्य, पार्किंग स्थल के प्रावधान के साथ परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर प्लेटफॉर्म की सतह का सुधार कार्य, नए शौचालय ब्लॉक का निर्माण, प्रतीक्षालय का सुधार कार्य, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टरों का प्रावधान और दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं में सुधार के कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- बारां स्टेशन पर: पार्किंग स्थल के प्रावधान के साथ परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्लेटफॉर्म संख्या 1 की सतह का सुधार कार्य, स्टेशन भवन और बरामदे का सुधार कार्य, जल निकासी से संबंधित कार्य, विभिन्न दिव्यांगजन सुविधाओं में सुधार, नए शौचालय ब्लॉकों का निर्माण, प्रतीक्षालय का सुधार कार्य, नए प्रतीक्षालय का निर्माण, बाउंड्री दीवार का सुधार कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर के प्रावधान से संबंधित कार्य पूरे किए जा चुके हैं। 12 मीटर चौड़े नए ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

- असारवा स्टेशन पर: नए प्रतीक्षालय, बुकिंग काउंटरों, बरामदे, शौचालय ब्लॉक के साथ नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, कॉनकोर्स क्षेत्र का कार्य पूरा किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण, प्लेटफॉर्म की सतह से संबंधित कार्य, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग क्षेत्र के विकास, दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं के प्रावधान का कार्य शुरू किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के कार्य सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों को पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार शुरू किया जाता है। किसी भी स्टेशन के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों को स्टेशन की कोटि/अवस्था/संभाले जाने वाले यातायात आदि के आधार पर किया जाता है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। निधि आबंटन और व्यय का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 के अन्तर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार अथवा स्टेशन-वार अथवा राज्य-वार।

राजस्थान राज्य पांच क्षेत्रीय रेलों अर्थात् उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4797 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है और जिसमें से अभी तक 3824 करोड़ रु. (दिसम्बर, 2025 तक) का व्यय उपगत किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य सात क्षेत्रीय रेलों, अर्थात् मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 5801 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 4581 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का व्यय उपगत किया गया है।

गुजरात दो क्षेत्रीय रेलों, अर्थात् उत्तर पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2081 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 1629 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2025 तक) का व्यय उपगत किया गया है।

हाई स्पीड रेल परियोजनाएँ

जहां तक हाई स्पीड रेल परियोजनाओं का संबंध है, जापान सरकार के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 कि.मी.) कार्यान्वयनाधीन है। यह परियोजना गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य और दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसमें 12 स्टेशन हैं। गुजरात खंड (लगभग 352 कि.मी. जिसमें दादरा और नगर हवेली शामिल हैं) में वापी और साबरमती के बीच आठ स्टेशनों वाला कॉरिडोर है जिसमें वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन हैं। दिसंबर 2025 तक इस परियोजना पर लगभग 86,939 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया जा चुका है।

हाई स्पीड रेल परियोजनाएँ अत्यधिक पूंजी-प्रधान हैं और किसी नई परियोजना को शुरू करने के संबंध में निर्णय कई कारकों पर आधारित होते हैं, जैसे तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय और आर्थिक क्षमता, यातायात की मांग और निधियों तथा वित्तपोषण विकल्पों की उपलब्धता आदि।

एलएचबी सवारी डिब्बे

एलएचबी सवारी डिब्बों की उपयोगिता विस्तार के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि आईसीएफ प्रकार के सवारी डिब्बों को सुरक्षित और अधिक आधुनिक एलएचबी सवारी डिब्बों से बदलने का कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया गया है। प्रौद्योगिकीय रूप से बेहतर एलएचबी सवारी डिब्बों में बेहतर यात्रा अनुभव, बेहतर सौंदर्य और हल्के डिजाइन, एंटी क्लाइम्बिंग विशेषताएं, एयर सस्पेंशन (द्वितीयक) विफलता संकेत प्रणाली सहित, स्टेनलेस स्टील शेल और डिस्क ब्रेक प्रणाली आदि जैसी विशेषताएं हैं।

वर्ष 2004-14 की तुलना में 2014-25 के दौरान एलएचबी सवारी डिब्बों का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है:

अवधि	विनिर्मित किए गए एलएचबी सवारी डिब्बे
2004-14	2,337 अदद
2014-25	42,677 अदद (18 गुना से अधिक)

इसके अलावा, भारतीय रेल द्वारा वंदे भारत और अमृत भारत गाड़ियां भी शुरू की गई हैं, जिनमें संवर्धित संरक्षा सुविधाएं और आधुनिक यात्री सुविधाएं हैं।

******